presently under execution by the Government of Punjab. As per the agreement reached in 1979 between the Government of Punjab and the Government of J&K and between the Government of Punjab and Government of Himachal Pradesh, 20 per cent of power generated at Thein Dam Power House would be made available to J&K at the cost of generation at power station bus-bar and 4.6 per cent of the power generated would be made available to Himachal Pradesh free of cost at power Station bus-bar. Another agreement was reached on 10th May, 1984 between the Chief Ministers of Haryana and Rajasthan, Governor of Punjab and the Government of India which provided inter-alia, for a Reference to the Supreme Court for its opinion on the question whether Haryana and Rajasthan were entitled to share in the power generated in five projects, including Thein Dam Project and if they were, the share of each State. Reference to the Supreme Court has not been made.

(d) and (e) The opinion of the Attorney General was taken into consideration while finalising the inter-State agreement of 10th May, 1984.

कोरबा तापीय विद्युत संयंत्र के लिये सहायक एककों की स्थापना

3634. **श्री अजीत जोगी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने दो संयंत्र, पहला कोरबा और दूसरा सिंगरौली में, स्थापित किये हैं परन्तु कोरबा स्थित तापीय विद्युत संयंत्र ने अभी तक सहायक उद्योग कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से हाथ में नहीं लिया है ;

(ख) उपर्युक्त तापीय विद्युत संयंत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली मदों के लिये सहायक उद्योगों की स्थापना करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सहायक उद्योग विकास संबंधी लघु उद्योग बोर्ड की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सहायक उद्योग लगाने हेतु सीमित कार्य करने अथवा कुछ न करने वाले उद्यमों की श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया है । सुपर ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन हेतु अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जो की प्राप्ति अधिकाशतः मुख्य संयंत्र उपस्कर के सप्लाईकर्ताओं द्वारा की जाती है । तथापि, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कोरबा परियोजना सहित अपनी अन्य परियोजनाओं के निकट उपयुक्त सहायक उद्योगों का पता लगाने के प्रयास किये हैं । किये गये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यूनिटों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता, निम्न प्रत्याशित अपक्रय तथा आसानी से सहायक उद्योगों को न लगा सकने वाली अद्यतन परिष्कृत प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न समस्याओं के कारण ये क्षेत्र सहायक उद्योग लगाने हेतु उपयुक्त नहीं हैं ।

3635. [*Transferred to the 1st September, 1988*].

राजस्थान में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

3636. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कितने और किन-किन कस्बों/शहरों में अब तक खाना पकाने की गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ; और

(ख) वर्तमान पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने कस्बों/शहरों में यह सुविधा प्रदान की जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) :

(क) तेल उद्योग ने राजस्थान के 54 कस्बों/शहरों में एल० पी० जी० सुविधा आरम्भ की है । इन शहरों/कस्बों के